जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:29 अंक:224 दिनांक:25-07-2024 गुरूवार मूल्य:1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट को इंडिया गठबंधन ने कुर्सी बचाओ बजट बताया है। गुरुवार को संसद की कार्यवाही शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर नारेबाजी की, विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया।

कुर्सी बचाने वाला बजट बताने पर विपक्ष पर भड़की वित्त मंत्री सीतारमण राज्यसभा में कांग्रेस को दे डाली चुनौती कहा-आप अपने हर बजट का भाषण दिखाएं

बजट पर दोनों सदनों में हंगामा....विपक्ष ने एक सुर में कहा कुर्सी बचाओ बजट

सोनिया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किया प्रदर्शन

नई दिल्ली (ईएमएस)। 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट को इंडिया गठबंधन ने कुर्सी बचाओ बजट बताया है। गुरुवार को संसद की कार्यवाही शुरू होते ही संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर नारेबाजी की, विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। इसमें सोनिया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव शामिल हुए। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा मोदी सरकार का ये बजट भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। इसमें कई राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह बजट सिर्फ अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए है... उन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया।

सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, समर्थन मूल्य किसान को ना देकर गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं...यूपी को बड़े सपने दिखाए थे, क्या मिला उत्तर प्रदेश को? लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है... विकास बिहार जा रहा है, तब उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रहे हैं?

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा, बजट देश का होता है, यह देश का बजट नहीं है। बजट सरकार बचाने के लिए नहीं होता है। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने कहा, हम बस इतना चाहते हैं कि वे (केंद्र) सच बोलें और देश के युवाओं को गुमराह न करें...वे नौकरियां कैसे पैदा करेंगे? उन्होंने राज्यों को भी गुमराह किया है। इतना ही नहीं बिहार को भी गुमराह किया है, राज्य को कुछ नहीं दिया गया है।

आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, ये कमाल का बजट बनाया है, जिसमें लगभग देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़कर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछता हूं कि वे राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया और अपने राज्य की सारी सीट दे दी उन राज्यों को बजट में क्या मिला? जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया, या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है, उन पर सब कुछ लुटा दिया। राजद सांसद मीसा भारती ने कहा, बिहार को मिला क्या है? युवाओं के लिए कुछ नहीं है, रोजगार पर कोई बात नहीं हुई है।

संसद में राहुल ने किसानों से मुलाकात की, बोले एमएसपी की कानूनी गारंटी देने सरकार पर दबाव बनाएंगे

नई दिल्ली (ईएमएस)। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संसद में राहुल के ऑफिस पहुंचा और लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा- कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। हमने आकलन किया है, ये बिल्कुल किया जा सकता है।

इस बारे में हमने किसान नेताओं के साथ बैठक की। हमने तय किया है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से चर्चा कर, हम सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएंगे। मुलाकात से कुछ देर पहले राहुल ने किसानों को संसद के अंदर नहीं आने देने का आरोप लगाया था। राहुल ने कहा था कि, हमने उन्हें (किसान नेताओं को) यहां मिलने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन वे उन्हें यहां (संसद में) नहीं आने दे रहे हैं। क्योंकि वे किसान हैं, शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं। इसके बाद किसानों को अंदर जाने की इजाजत मिली।

किसान 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे

22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा था कि वे देशभर में मोदी सरकार के पुतले जलाएंगे। एमएसपी गारंटी को कानूनी बनाने की अपनी कानून की गारंटी, ऋण माफी, फसल बीमा, किसानों और खेतिहर मजदूरों की पेंशन, बिजली के निजीकरण को वापस लेने समेत अन्य मांगों को पूरा करने के लिए नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। इसके अलावा विपक्ष द्वारा निजी विधेयकों का समर्थन करने के लिए मार्च भी निकालेंगे। प्रदर्शनकारी किसान 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और नए क्रिमिनल बिल की कॉपियां भी जलाएंगे। किसान संगठनों ने कहा था कि किसानों का दिल्ली चलो मार्च 31 अगस्त को 200 दिन पूरा करेगा। संगठनों ने किसानों से पंजाब-हरियाणा के खनौरी-शंभू बॉर्डर पर पहुंचने की अपील भी की है।

कुर्सी बचाने वाला बजट बताने पर विपक्ष पर भड़की वित्त मंत्री सीतारमण

राज्यसभा में कांग्रेस को दे डाली चुनौती कहा-आप अपने हर बजट का भाषण दिखाएं

नई दिल्ली,(ईएमएस)। मंगलवार को देश सदन में देश का आम बजट वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किया था। इस बजट को लेकर बुधवार को संसद में जोरदार हंगामा हो गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि यह बजट कुर्सी बचाने वाला है। खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बजट में ना तमिलनाडु, न कर्नाटक, न हरियाणा, न राजस्थान, और ना ओडिशा को कुछ मिला है। किसी को खुश करने के लिए यह बजट है। खड़गे के इस आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भड़क गईं और बजट में राज्यों के नाम पर कांग्रेस को चुनौती दे डाली और सवाल किया कि क्या आपने अपने सभी बजट भाषणों में सभी राज्यों का नाम लिया था?

विपक्ष का आरोप है कि इस बजट में केवल दो राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश को ही फंड दिया गया बाकी राज्यों को कुछ खास नहीं मिला दिया। उधर सीतारमण ने इस आरोप को 'अपमानजनक' करार देते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों के मन में यह धारणा बनाने की कोशिश कर रही है कि दूसरे राज्यों को कुछ नहीं दिया गया है। सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आप अपना हर बजट भाषण हमें दिखाइए कि आपने अपने समय में हर राज्य का नाम लिया था। हमने अपने बजट भाषण में सभी राज्यों का नाम नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने उन राज्यों को कुछ नहीं दिया है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने वधावन में एक बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया था, लेकिन बजट में महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया गया तो इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया है? अगर भाषण में किसी विशेष राज्य का नाम लिया जाता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि सरकार के कार्यक्रम इन राज्यों में नहीं जाते हैं? यह कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का लोगों को यह धारणा बनाने का एक जानबूझकर प्रयास है कि अन्य राज्यों को कुछ नहीं दिया है। यह एक अपमानजनक आरोप है।

वित्त मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र को हमने 6000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन भाषण में इसका जिक्र नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल को 10 साल में कई योजनाएं दी गईं, लेकिन बंगाल ने केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया और अब वे सवाल कर रहे हैं। सीतारमण के इस आरोप पर बंगाल की सांसद भड़क गईं और फिर सदन में हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले खड़गे ने विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभालते हुए सरकार पर आरोप लगाया, 'कुर्सी बचाने के लिए यह सब हुआ ष्ठ हम इसकी निंदा करेंगे और इसका विरोध करेंगे। इंडिया गठबंधन के सभी दल इसका विरोध %ह्र*ष्ठरू* संतुलन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा?' इसके साथ ही विपक्षी दल के सभी सदस्य राज्यसभा से वॉकआउट कर गए।

किसान आंदोलन के चलते बंद शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा

चंडीगढ़ (ईएमएस)। हरियाणा और पंजाब के बीच अंबाला के पास स्थित शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा सरकार ने इसे 5 महीने से बैरिकेडिंग कर बंद कर रखा है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। यहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक स्वत्रंत कमेटी गठित करने का प्रस्ताव करता है। इसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। ये किसानों और सरकारों से संपर्क कर उनकी मांगों का ऐसा व्यावहारिक समाधान खोज सकेगी जो सभी को स्वीकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में पंजाब और हरियाणा सरकारों से स्वतंत्र समिति के लिए सदस्यों के नाम सुझाने को कहा।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि अगर किसान बिना ट्रैक्टरों से किसान दिल्ली जाते हैं, तो सरकार का क्या कदम रहेगा। वहीं, कोर्ट ने पूछा कि क्या उन्होंने किसानों से बातचीत की कोशिश की है। कोर्ट ने पूछा कि किसान सोचते है कि मंत्री सरकार की बात करेंगे। ऐसे में क्या कोई सांझे व्यक्ति के माध्यम से बातचीत की कोशिश की गई। नेशनल हाईवे को कब तक बंद रखोगे।

हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने अदालत में कहा कि स्वतंत्र कमेटी का सुझाव हम सरकार के समक्ष रखेंगे। बॉर्डर सील से आर्थिक नुकसान हो रहा है, यह बात पंजाब सरकार की तरफ से रखी गई है। फिलहाल यह बार्डर नहीं खुल रहा है। हरियाणा के वकील ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर बातचीत की जा रही है। वहीं, उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जिस तरह के वाहन हैं, वह काफी चौंकाने वाले है। वहां पर कुछ ऐसे वाहन है, जिन्हें टैंकर के रूप में कन्वर्ट कर रखा है। वहां पर क्रेन है। किसानों को मनाने की कोशिश की जा रही हैं। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि आप सरकार है। ऐसे में आप किसानों से मिले, समस्या का हल निकालने की कोशिश करे।

भारत-बांग्लादेश के बीच व्यापार फिर शुरू, हिंसा के चलते दो दिन के लिए किया गया था बंद

कोलकाता : पिछले दिनों बांग्लादेश में पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। जो विवादास्पद कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर बांग्लादेश कस्टम डयूटी विभाग के अधिकारी अवकाश पर चले गए थे। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार रुक गया था।

भारत-बांग्लादेश के बीच बुधवार से व्यापार फिर शुरू कर दिया गया। पड़ोसी बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण के विरोध में हुई हिंसा को लेकर दो दिन के लिए दोनों देशों के बीच व्यापार बंद कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि बांग्लादेश कस्टम डयूटी विभाग ने काम फिर से शुरू कर दिया। वहां इंटरनेट की बहाली होने के बाद पेट्रापोल, गोजाडांगा, फुलबारी और महादीपुर समेत सभी बंदरगाहों से व्यापार शुरू कर दिया गया।

पिछले दिनों बांग्लादेश में पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। जो विवादास्पद कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, जिसमें 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सैनिकों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण था। इसे लेकर बांग्लादेश कस्टम डयूटी विभाग के अधिकारी अवकाश पर चले गए थे। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार रुक गया था।

लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (पेट्रापोल) के प्रबंधक कमलेश सैनी ने बताया कि पेट्रापोल सीमा से बुधवार से व्यापार शुरू कर दिया गया। बेनापोल की ओर से कार्गो आवाजाही शुरू कर दी गई। पहले खराब होने वाले माल से लदे ट्रकों को प्राथमिकता दी गई। बेनापोल स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव सजेदुर रहमान ने बताया कि 220 ट्रक पेट्रापोल से बांग्लादेश में दाखिल हुए। इनमें से 27 ट्रक बांग्लादेश पहुंचे।

पश्चिम बंगाल निर्यातक समन्वय समिति के सचिव उज्ज्वल साहा ने कहा कि पहले दिन भीड़भाड़ के चलते काफी ट्रक देरी से सीमा में दाखिल हुए। इसके कुछ दिनों में सामान्य होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बोनगांव स्थित पेट्रापोल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहां से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार होता है। औसतन 400-450 ट्रक सामान लेकर भारत से पेट्रापोल भूमि बंदरगाह को पार करते हैं, जबकि 150-200 ट्रक हर दिन बांग्लादेश से भारत आते हैं।

'नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगा तेलंगाना', विधानसभा में सीएम रेवंत रेड्डी ने की घोषणा

हैदराबाद : सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा राज्य की बकाया धनराशि भी जारी नहीं की गई। इसके विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मणा सीतरमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया था। इसके बाद वीपक्षी गठबंधन इंडिया के कुछ नेताओं ने इसे 'सरकार बचाओ बजट', तो किसी ने 'भेदभावपूर्ण' बजट करार दिया। इसके बाद कांग्रेस ने 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का एलान किया था। बताया गया है कि नीति आयोग की बैठक में कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भाग नहीं लेंगे। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बजट के दौरान तेलंगाना के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा राज्य की बकाया धनराशि भी जारी नहीं की गई। इसके विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में सरकार के निर्णय की घोषणा की।

तेलंगाना के सीएम ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, मैं तेलंगाना के हितों को नुकसान पहुंचाने और तेलंगाना की बकाया धनराशि जारी न करने के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहा हूं।' विधानसभा में दिन भर चली बहस के बाद केंद्रीय बजट में तेलंगाना के प्रति केंद्र के कथित भेदभाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। उधर, भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव का विरोध किया।

पैकेज के दम पर चल रही मोदी सरकार, बजट में हुआ साफ : अखिलेश

नई दिल्ली (ईएमएस)। आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं। धरना-प्रदर्शन में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि सरकार बचाने के लिए पैकेज दिया जा रहा है। मंगलवार को जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से साफ दिखता है कि मोदी सरकार कितनी कमजोर है। हम लोग किसान के लिए समर्थन मूल्य मांग रहे थे। किसान-गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं। लेकिन, यह सरकार उन्हें पैकेज दे रही है, जो सरकार चलवा रहे हैं। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भेदभाव न किया जाए। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिला? बिहार की बाढ़ रोकनी है, तब भारत सरकार को नेपाल से बात करनी पड़ेगी। लेकिन, मोदी सरकार अगर उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोकती है, तब बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। जो एक्सप्रेसवे बिहार को दिया गया है, उस एक्सप्रेसवे को अगर यूपी से भी जोड़ दिया जाता तब ज्यादा बेहतर होता। हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन, उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव स्वीकार नहीं होगा। अखिलेश ने कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल में नौजवानों की नौकरी और वेतन छीनी। अब आप युवाओं को पांच हजार की नौकरी देना चाहते हैं, वहां भी तब जब सरकारी कर्मचारी आठवां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे हैं।

संपत्ति बेचने पर कटेगा टीडीएस, क्रेता होगा जिम्मेदार

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत सरकार ने 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 50 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति बेचने पर एक फ़ीसदी टीडीएस काटने के प्रावधान किया है। अचल संपत्ति की खरीद बिक्री में कितने ही क्रेता और विक्रेता हों। 50 लाख से अधिक की संपत्ति खरीदने वाले क्रेता को 1ङ्क टीडीएस काटकर आयकर विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी तय की गई है। आयकर अधिनियम की धारा 194-1ए मैं कृषि भूमि को छोड़कर अन्य अचल संपत्ति बेचने पर अब टीडीएस जमा करना अनिवार्य होगा।

बिहार में पेपर लीक पर 10 साल की सजा

1 करोड़ का जुर्माना; विधानसभा से विधेयक पास; सदन से विपक्ष का वॉकआउट

पटना (ईएमएस)। बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक, अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी।

नए कानून में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। विपक्ष के हंगामा को देखते हुए सदन गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बिल को मानसून सत्र के दूसरे दिन ही पेश होना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सरकार इसे पेश नहीं कर पाई। सदन में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।

नीतिश ने फिर खोया आपा, महिला विधायक से कहा....अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो

पटना (ईएमएस)। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। नीतीश विधानसभा में बोल रहे थे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी ने 2005 के बाद महिला को आगे नहीं बढ़ाया। इस बीच आरजेडी विधायक रेखा देवी ने अपनी प्रतिक्रिया देने की कोशिश की। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। हम कह रहे हैं चुपचाप सुनों। वहीं, रेखा देवी ने बयान का विरोध कर गलत बयान बताया है।

दरअसल मुख्यमंत्री बजट पर वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर बैठकर पूरी बात सुन लीजिएगा, तब आपको ठीक लगेगा। तभी वे भड़क कर बोले ऐ सुनिए। अरे हमको सबको बुलाए हैं, मेरी इच्छा थी न। सारी पार्टियों को आप लोग भी साथ थे, ये भी। सुनिए! चुप रहिए। इसी बीच नीतीश तेज आवाज में राजद विधायक रेखा देवी से बोले कि अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। अरे बोल रही है कि कहां से आते। इन लोगों के साथ जो है... ये लोग कोई (राजद) महिला को आगे बढ़ाया था। अरे हम 2005 के बाद न कोई महिला को आगे बढ़ाए हैं। बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चुपचाप सुनों।

इसके साथ ही जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बजट जैसी चीज राबड़ी देवी की समझ से बाहर है। उन्हें साइन करना आता नहीं, बजट पर क्या बोलेंगी।

नेपाल में प्लेन कैश,18 लोगों की मौत

-काठमांडू से उड़ान भरते ही विमान में झटका लगा, फिर आग लग गई

काठमांडू (ईएमएस)। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया है। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई है। वहीं घायल पायलट कैप्टन मनीष शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर यह क्रैश हो गया। 9एन-एएमई प्लेन सौर्य एयरलाइन्स का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे।

काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी। इसे तुरंत बुझा दिया गया। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। हालांकि, हादसा किस वजह से हुआ इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है।

BSF महानिदेशक बोले- 10 फीसदी आरक्षण के साथ आयु सीमा में छूट भी

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है और इससे सेना की ताकत बढ़ेगी। पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ और सीआईएसएफ की भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्व अग्निवीरों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की भर्तियों में दस फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें शारीरिक मानदंड (फिजिकल) में भी छूट दी जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। गृह मंत्रालय के अनुसार, बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल का कहना है कि पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण के साथ साथ आयु सीमा में छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि चार वर्ष के अनुभव वाले पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ के लिए उपयुक्त पाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है और इससे सेना की ताकत बढ़ेगी।

उधर, सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने भी इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के बाद सीआईएसएफ भी अपने बल में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए तैयार है।

करंट लगने से निलेश की हुई थी मौत, आतिशी ने मुख्य सचिव को दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली : दिल्ली के पटेल नगर में एक आईएएस अभ्यर्थी की करंट लगने से मौत हो गई थी। मामले में मंत्री आतिशी ने सख्त रुख अपनाया है। बिजली मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को इस घटना की जांच करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कारवाई करने के निर्देश दिए हैं।

पटेल नगर में करंट लगने से आईएएस अभ्यर्थी के मौत होने की घटना पर बिजली मंत्री में सख्त रुख अपनाया है। बिजली मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को इस घटना की जांच करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कारवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कारवाई की जाये और उससे संबंधित रिपोर्ट अगले दो दिनों के भीतर सौंपी जाये। साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव को भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नीतिगत सुझाव मांगे हैं, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोकथाम लगाई जा सके।

सहायता अनुग्रह राशि को लेकर बिजली मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि मृतक के परिजनों को सहायता अनुग्रह राशि देने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए और कल शाम पांच बजे तक इसका प्रस्ताव उन्हें सौंपा जाए। आतिशी ने कहा कि एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पटेल नगर इलाके में करंट लगने से 26 वर्षीय आईएएस अभ्यर्थी की जान चली गई। सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के कारण एक युवा की जान चली गई। ऐसे में मौत के कारण का पता लगाने की जरूरत है और दोषियों पर जिम्मेदारी तय कर सख़्त कारवाई करने की जरूरत है, ताकि यह भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सके।

'लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने की मुझे मारने की कोशिश', गोलीबारी मामले में बोले सलमान खान

मुंबई : अभिनेता सलमान ने अपने घर के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस के सामने जो बयान दिया है, अब वह सामने आ गया है। अभिनेता के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने उन्हें और उनके परिवार को मारने के मकसद से उनके घर पर फायरिंग की थी।

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर दो लोगों ने फायरिंग कर सनसनी मचा दी थी। 14 अप्रैल की इस घटना पर अब अभिनेता का बयान सामने आ गया है। सलमान ने पुलिस को बताया है कि उनका मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने उनके घर पर गोलीबारी की थी। इसके पीछे का उद्देश्य उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मारना था।

अभिनेता का बयान इस घटना के संबंध में मुंबई पुलिस की ओर से अदालत में दायर आरोपपत्र का हिस्सा है। सलमान ने पुलिस को बताया कि 14 अप्रैल की सुबह जब वह गैलेक्सी अपार्टमेंट स्थित अपने घर में सो रहे थे तो उन्हें पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी। उन्होंने बताया कि उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस ने सुबह करीब 4.55 बजे उन्हें बताया कि मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने पहली मंजिल की बालकनी पर गोलीबारी की है।

सलमान ने अपने बयान में कहा कि पहले भी उन्हें और उनके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि उनके अंगरक्षक ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में गोलीबारी के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। अभिनेता ने बताया कि जनवरी 2024 में दो अज्ञात व्यक्तियों ने फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर पनवेल के निकट उनके फार्महाउस में जबरन घुसने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत के समक्ष गोलीबारी मामले में 1,735 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था। इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इसे मामला आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त माना था।

इस मामले में विक्की कुमार गुप्ता, सागर कुमार पाल, सोनू कुमार बिश्नोई, अनुज कुमार थापन (दिवंगत), मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। थापन ने कथित तौर पर गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली थी। वहीं, अन्य पांच अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

आंध्र प्रदेश के स्पेशल पैकेज पर भड़की तेलंगाना सरकार, विरोध में उतरे विपक्षी सांसद

हैदराबाद(ईएमएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को केंद्रीय बजट को लेकर निराशा जताई और आरोप लगाया कि इसमें तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 8 कांग्रेस सांसद इस बजट में तेलंगाना की अनदेखी को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। सीएम ने कहा, हमारे 8 कांग्रेस सांसद निश्चित रूप से अन्य सांसदों के साथ अपना विरोध व्यक्त करेंगे। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम केवल आंध्र प्रदेश के लिए फंड देने के बारे में नहीं है, बल्कि तेलंगाना के बारे में भी है। विधानसभा में, हम प्रश्नकाल के बाद इस अन्याय पर चर्चा करेंगे। मैं 8 भाजपा सांसदों और एआईएमआईएम सांसदों से अनुरोध करता हूं कि वे 8 कांग्रेस सांसदों के विरोध कार्यक्रम में भाग लें। सभी को राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के लिए लड़ना चाहिए। विरोध प्रदर्शन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद भी भाग ले सकते हैं। सीएम रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को बजट में स्पेशल पैकेज दिए जाने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि आंध्र के साथ तेलंगाना को भी विशेष आवंटन दिया जाना चाहिए था।

इससे पहले भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी.रामाराव ने भी केंद्रीय बजट को लेकर निराशा जताते हुए कहा कि इसमें तेलंगाना के लि

जन हितैषी

राष्ट्रपति चुनाव से वाइडेन हटे, ट्रंप को भारतवंशी कमला हैरिस से मिलेगी कड़ी टक्कर

राष्ट्रपति पद के चुनाव से हटने की घोषणा वर्तमान राष्ट्रपति जो वाइडेन ने कर दी है। वाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार थी। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, डेमोक्रेटिक पार्टी के किंग मेकर बनकर उभरे हैं। उन्होंने वाइडेन को राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दी थी। पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भी वाइडेन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटने के बाद,कमला हैरिस को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। 19 अगस्त को शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की बैठक होगी। जिसमें 4000 से अधिक डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अधिकृत नाम की घोषणा शिकागो कन्वेंशन मे होगी। कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई चुनौती देना चाहेगा। तो उसे 600 प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त करके उम्मीदवारी का दावा करना होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव मे लगभग 105 दिन बाकी हैं। जिस तेजी के साथ अमेरिका में राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। उसको लेकर यह कहा जा रहा है, जो वाइडेन के चुनाव मैदान से हटने के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो वाइडेन कमजोर साबित हो रहे थे। पिछले वर्षों में उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस ने अपने कामकाज को लेकर अमेरिका में सभी वर्गों में लोकप्रियता हासिल की है। कमला हैरिस भारतवंशी है। डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतवंशी महिला के पति को अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय मूल के और अश्वेत वर्ग के लोगों में कमला हैरिस को काफी गंभीरता से लिया जाता है। वह एक सूझबूझ वाली महिला हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में पिछले एक माह में जिस तरह के परिवर्तन अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं। उससे लग रहा है, अमेरिका नया इतिहास बनाने जा रहा है। पूर्व विदेश मंत्री हेलरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति पद का चुनाव 2016 में लड़ा था। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव हराया था। अमेरिका के इतिहास में अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है। अमेरिका में दूसरी बार महिला, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के लोगों का समर्थन पाने के लिए पिछले चुनाव के पहिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति रहते हुए अच्छे संबंध बनाए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार अमेरिका में अबकी बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए थे। उसके बाद भी ट्रंप पिछला चुनाव हार गए थे। कमला हैरिस के चुनाव मैदान में आने के बाद, राष्ट्रपति चुनाव के सारे समीकरण बदल गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई मामले अदालत में लंबित है। कुछ मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है। अमेरिका में वह कट्टरबाद के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से दुनिया के देशों में दक्षिणपंथी विचारधारा कमजोर हो रही है। ऐसी स्थिति में कमला हैरिस, राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रम्प को कड़ी चुनौती देंगी। ट्रम्प को जो समर्थन वाइडेन के कारण अभी मिल रहा था। निश्चित रूप से अब कमला हेरिस से उन्हें चुनौती मिलना तय है। ट्रम्प की लोकप्रियता में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का समर्थन कमला हैरिस को मिल रहा है। भारतीय मूल के नागरिकों का समर्थन भी कमला हैरिस को बड़े पैमाने पर मिलना तय माना जा रहा है। जो वाइडेन के चुनाव मैदान से हट जाने के बाद, अमेरिका की राजनीति में बड़ा बदलाव आ गया है। जो वाइडेन के सामने ट्रंप काफ़ी मजबूत थे। जिस तरह से चुनाव के बीच जो वाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। उसने सारे समीकरण एक ही झटके में बदल दिए हैं। अमेरिका के इतिहास में 1968 के बाद यह पहला मौका है। जब किसी राष्ट्रपति ने चुनाव मैदान से हटने की घोषणा की है। अमेरिकी इतिहास में जो वाइडेन सबसे ज्यादा उम्र वाले राष्ट्रपति हैं। अभी उनकी उम्र 81 वर्ष की है। वह कई बीमारियों के शिकार हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी को जो चंदा मिला था। वह चंदा जो- वाइडेन और कमला हैरिस के नाम पर मिला था। राष्ट्रपति वाइडेन ने उत्तराधिकारी के रूप में कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया है। जिसके कारण 2007 करोड रुपए का जो चंदा डेमोक्रेटिक पार्टी के पास है। इसका उपयोग चुनाव के लिए कमला हैरिस कर सकेंगी। कमला हेरिस की उम्मीदवारी घोषित होने पर उन्हें 407 करोड़ का नया चंदा मिला है। जो उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने वाला है। निश्चित रूप से कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर देगी। अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड भी कमला हैरिस के नाम पर बनने की संभावना जताई जा रही है। इस तरह की चर्चा अमेरिका में होने लगी है। निश्चित रूप से इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं रहा।

अपना गठबंधन अपनी मजबूरियां और आम बजट

मोदी 3.0 का पहला बजट सामने है। कई राज्य खाली हाथ हैं। लेकिन गठबन्धन धर्म की रीत निभाता यह बजट हमेशा की तरह आंकड़ों, गणित और पहेलियों में उलझा हुआ है। आम आदमी बस इतना समझता है कि क्या सस्ता हुआ, क्या मंहगा, किसे क्या मिला और सीधे-सीधे टैक्स में कितनीबचत हुई?अभी इतनासमझ आ रहा है कि मोबाइल और चार्जर सस्ते हुए और सोने-चांदी केदाम भी थोड़ा घटेंगे। प्राइवेट जॉब में युवाओं को आस है।टॉप देशी 500 कंपनियां 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका देंगी और 5 हजार रुपए मासिक, और एकमुश्त 6 हजार की अतिरिक्त सरकारी मदद तथा इस दौरान कैंपस सुविधा मिलेगी।यह नियमित नौकरी तो नहीं होगी लेकिनपीएम इंटर्नशिप स्कीम की पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा।वहीं 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग की तैयारी भी है।

रेलवे को रेकॉर्ड पैसा देने के बावजूद खास चर्चा नहीं हुई। सुरक्षा पर ही ध्यान रहा। बीते वित्त वर्ष में 700 करोड़ से अधिक लोगों ने सफर किया। चालू वित्त वर्ष में 2500 अतिरिक्त जनरल कोच बनेंगे। गठबंधन धर्म के बावजूद आम आदमी की खास जरूरत जिसमेंसीनियर सिटीजन, वेटिंग लिस्ट और यात्री सुविधाओं का जिक्र तक नहीं हुआ।

टीडीएस नियमावली आसान होगी और क्रिमिनल लॉ बाहर होंगे। जीवन बीमा पॉलसियों जिनका सम एश्योर्ड 10 प्रतिशत से ज्यादा हैं उनकी मैच्योरिटी पर भी 5 प्रतिशत टीडीएस कटता है जो घटाकर अब 2 प्रतिशत किया गया है।रियल एस्टेट भी बजट से निराश है। अब प्रॉपर्टी दो साल के लांग टर्म की श्रेणी में आएगी। पहले तीन साल में थी। मतलब इस सेक्टर को इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा।

भाजपा ने खास सहयोगियोंबाबू नीतिशऔर चंद्रबाबू को साधा जरूर लेकिन स्पेशल स्टैटस का दर्जा नहीं दिया।उनकीविभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर धनवर्षा खूब की। बाढ़ प्रभावित राज्यों बिहार, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, असम सिक्किम को मदद का ऐलान हुआतो मणिपुर में बाढ़ विस्थापितों को राहत या पुनर्वास की चर्चा तक नहीं हुई।उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और गोवाको बजट में कुछखासमिला नहीं।शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष तो और दीगर जरूरतों पर मरहम की घोषणाओं का महज इंतजार होता रहा।

मध्यम तबके को साधने की कवायद जरूर दिखी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल (पीपीपी) के तहत 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में औद्योगिक कामगारों खातिर डॉरमेट्री जैसी सुविधाएं तो आधी आबादी कोसाधनेहेतुउनके पोषण से लेकर स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल व शिशु गृह तैयार करने पर घोषणा हुई। इससे महिलाओंकाघर व काम के बीच बेहतर ढ़ंग से तालमेल होगा। वहीं एक करोड़ घरों को सोलर पैनल के जरिए 300 यूनिट फ्री बिजली की जगमगाहट का इंतजार है।

इस बजट से शेयर बाजार जरूर असंतुष्ट दिख रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स जो पहले 15 प्रतिशत था अब 20 प्रतिशत हो गया है।फ्यूचर और ऑप्शन पर सिक्योरिटी एण्ड ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ गया है। निश्चित रूप से इसका नकारात्मक परिणाम भी भाषण के साथ शेयर बाजार में दिखा।पूरे बजट को देखने से यह लगता है कि सरकार का फोकस नई टैक्स प्रणाली को भविष्य में मजबूती से लाना है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16 में मानक कटौती का प्रावधान है जिसका ज्यादा फायदा नौकरीपेशा लोगों को ही होता है। इसमें एक तय राशि को ही टैक्सेबल आय से घटाया जाता है जिससे टैक्स पेयर की देनदारी कम जाती है। इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। बाद में इसे खत्म कर दिया गया लेकिन 2018 में स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर शुरू हुआ। अब इसका लाभ नई और पुरानी कर प्रणालियों में लिया जा सकता है। इस बजट में यह कटौती 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दी गई है।

कृषि क्षेत्र में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए अगले दो वर्षों में राजी किया जाएगा। जलवायु अनुरूप फसल उगाने के साथ सब्जी उत्पादन बढ़ाने हेतु कलस्टर विकसित होंगे।वहीं किसान संगठन से जुड़े नेताओं ने कहा है तो फिर उर्वरकों और रसायनों पर सब्सीडी कैसी? निश्चित रूप से बढ़ती मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए कृषि क्षेत्र अहम है। इसलिए सबको लगता था कि इस पर ज्यादा चर्चा होगी।

बजट में पूर्वी क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया है और पर्यटन की संभावनाओं के नाम पर बिहार खातिर बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुईं। विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के व्यापक विकासितकर विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थलों में बदलने की बात कही गई।राजगीर और नालंदा विश्वविद्यालय के लिए व्यापक विकास की पहल है। नए हाथ आए राज्य ओडीशा की प्राकृतिक सुन्दरता के मद्देनजर वहां भी पर्यटन हब बनाने की घोषणा हुई।

मध्यम आय वर्ग बजट से ज्यादा संतुष्ट नहीं दिख रहा है। रसोई, सिलेण्डर का खर्चा बढ़ता जा रहा है। रिटायर्ड और मौजूदा सरकारी कर्मचारी भी बड़ी उम्मीदें पालेथे। हां कैंसर मरीजों को जरूर महंगी दवाओं से राहत मिलेगी। जबकि चुनावी राज्यों के हाथ मायूसी लगी। महाराष्ट्र, हरियाणा का जिक्र तक नहीं हुआ तो जम्मू-कश्मीर और झारखण्ड का नाम आया जरूर लेकिन वहां चुनावों केमद्देनजर खास कुछ मिला नहीं।

बिहार-आंध्रप्रदेश की तमाम योजनाओं पर 74 हजार करोड़ की धनवर्षा से लगता नहीं कि यह बजट सरकार के अपने अरमानों पर ज्यादा केन्द्रित है? फिर भी 7.75 लाख रुपए आय तक टैक्स नहीं लगने और कुल आय पर स्टैण्डर्ड 50 हजार से बढ़ाकर 75 करने से कुछ फायदा तो तय है।अब यह ऊंट के मुंह में जीरा होगा या जीरे मे ऊंट मुंह मारेगा? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। (लेखक - ऋतुपर्ण दवे/ईएमएस)

असुरक्षा का भाव चमका रहा है बाबाओं का धंधा

उत्तरप्रदेश के हाथरस जिले में भगदड़ में कम से कम 121 लोग मारे गए। इनमें से अधिकांश निर्धन दलित परिवारों की महिलाएं थीं। भगदड़ भोले बाबा उर्फ़ नारायण साकार हरी के सत्संग में मची। भोले बाबा पहले पुलिस में नौकरी करता था। बताया जाता है कि उस पर बलात्कार का आरोप भी था। करीब 28 साल पहले उसने पुलिस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और बाबा बन गया। कुछ साल पहले उसने यह दावा किया कि वह कैंसर से मृत एक लड़की को फिर से जिंदा कर सकता है। जाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं हो सका। बाद में बाबा के घर से लाश के सड़ने की बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस से शिकायत की। इस सबके बाद भी वह एक सफल बाबा बन गया, उसके अनुयायियों और आश्रमों की संख्या बढ़ने लगी और साथ ही उसकी संपत्ति भी।

हालिया घटना के बाद बाबा के कुछ चेले-चपाटों को पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया है। मगर बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है। भगदड़ इसलिए मची क्योंकि यह प्रचार किया गया था कि जिस मिट्टी पर बाबा चलता है, वह बहुत से रोगों को ठीक कर सकती है। सत्संग ख़त्म होने के बाद बाबा जब वापस जा रहा था तब जिस मिट्टी पर उसके कदम पड़े थे, उसे उठाने के लिए भक्तगण लपके जिससे भगदड़ मच गयी और बड़ी संख्या में लोग अपनी जान से हाथ खो बैठे। यह बाबा कितना लोकप्रिय हैं यह इससे जाहिर है कि सत्संग में 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गयी थी मगर वहां करीब डेढ लाख लोग पहुँच गए।

भारत में बाबा कोई नई चीज़ नहीं हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बाबा केवल भारत में पाए जाते हैं। हाँ यह ज़रूर है कि पिछले कुछ सालों से उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। भारत में सैकड़ों बाबा हैं और वे देश के हर हिस्से में पाए जाते हैं। कुछ बाबाओं की ख्याति विशिष्ट क्षेत्रों में है। आसाराम बापू और गुरमीत राम रहीम इंसान जैसे कुछ बाबा बलात्कार और हत्या करने के कारण जेलों की हवा खा रहे हैं। एक अन्य सफल बाबा हैं बाबा रामदेव, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का मज़ाक उड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जम कर फटकार लगाई थी। श्री श्री रविशंकर पर यमुना नदी को प्रदूषित करने का आरोप है। जग्गी वासुदेव के कई आश्रमों में आपराधिक गतिविधियाँ होने के चर्चा है। बाबा अलग-अलग प्रकार के हैं मगर कुछ बातें सभी बाबाओं में समान हैं। सभी बाबाओं के पास ढेर सारी संपत्ति और धन है, सभी बाबा अंध श्रद्धा को बढ़ावा देते हैं और सभी का आत्मविश्वास अचंभित करने वाला है।

यद्यपि इस बारे में कोई पक्की जानकारी तो उपलब्ध नहीं है मगर मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बाबाओं की संख्या और उनके प्रभाव में पिछले कुछ दशकों में तेजी से वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का धर्म की राजनीति के बढ़ते बोलबाले से अंतर्संबंध स्थापित करना भी आसान नहीं है। यह सही है कि दूसरे देशों में भी बाबाओं की तरह के लोग हैं। अमरीका में केरिसमेटिक ईसाई आन्दोलन है तो कुछ मुस्लिम देशों में भी चमत्कार करने वाले फ़क़ीर हैं। मगर भारत में बाबाओं का जितना प्रभाव है, उतना किसी और देश में नहीं है। सारे बाबा धर्म का चोला ओढ़े रहते हैं। वे संस्थागत हिन्दू धर्म के पुरोहित वर्ग से नहीं होते। उनमें से अधिकांश अपने बल पर सफलता हासिल करते हैं। वे लोगों का दिमाग पढने और अपने अनुयायियों की कमजोरियों का फायदा उठाने में सिद्धहस्त होते हैं।

मगर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि लोग आखिर बाबाओं की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? निसंदेह, बाबा अपनी मार्केटिंग बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं मगर यह भी सही है कि उनके भक्तों की अपनी कमजोरियां होती हैं जिनके चलते वे इन धोखेबाजों के चंगुल में फँस जाते हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जो गंभीर समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। उनकी समस्यायों का कोई हल उनके पास नहीं होता। उन्हें दरकार होती है सांत्वना के कुछ शब्दों की, किसी ऐसे व्यक्ति की जो उन्हें यह भरोसा दिला दे कि बाबा की चरणरज माथे से लगाने से, उनके प्रति पूर्ण समर्पण से या उनके बताए उपाय करने से उसकी समस्या हल हो जाएगी। बाबाओं के आसपास जो भीड़ जुटती है, उनमें बहुसंख्या ऐसे लोगों की होती है जो असुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं। राजनेताओं से सांठगाँठ भी उनकी सफलता में योगदान देती है। गुरमीत राम रहीम महीनों पर पैरोल पर रहता है, विशेषकर चुनावों के समय। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर अपनी पूरी मंत्रीपरिषद के साथ गुरमीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे।

परन्तु मुख्यतः अनुयायियों में असुरक्षा का भाव उन्हें बाबाओं की ओर आकर्षित करता है। जितनी ज्यादा असुरक्षा, बाबाओं के प्रति उतनी ज्यादा श्रद्धा। और जितनी ज्यादा श्रद्धा, विवेक और तार्किकता से उतनी ही दूरी। असुरक्षा का कारक कितना महत्वपूर्ण है यह हम इससे भी समझ सकते हैं कि जिन देशों में आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा कम है, वहां धर्म का प्रभाव भी कम होता जा रहा है। वैश्विक शोध संस्थान पीईडब्ल्यू का निष्कर्ष हैः इस मामले में संयुक्त राज्य अमरीका अकेला नहीं है। पश्चिमी यूरोप के देशों के नागरिक सामान्यतः अमरीकियों से भी कम धार्मिक हैं क्योंकि वे उस राह पर अमरीका से कई दशक पहले चल पड़े थे। धर्म का घटता प्रभाव आर्थिक दृष्टि से उन्नत अन्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी देखा जा सकता है।

मिशिगन विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर पोलिटिकल स्टडीज के प्रोफेसर रोनाल्ड इंगोहार्ट अपनी पुस्तक गिविंग अप ऑन गॉड (पृष्ठ 110-111) में लिखते हैं, सन 2007 से लेकर 2019 तक जिन 49 देशों का हमनें अध्ययन किया, उनमें से 43 में उस अवधि में लोगों में धार्मिकता घटी है। धार्मिक आस्था में कमी केवल उच्च आय वाले देशों तक सीमित नहीं है। ऐसा पूरी दुनिया में हुआ है। ऐसे लोगों की संख्या बढती जा रही है जिन्हें नहीं लगता कि उनके जीवन को अर्थपूर्ण बनाने और उन्हें सहारा और संबल देने के लिए धर्म ज़रूरी है। लम्बे समय से यह कहा जाता रहा है कि अमरीका इस बात का प्रमाण है कि आर्थिक रूप से उन्नत देश भी अत्यंत धार्मिक हो सकता है। मगर अन्य धनी देशों की तरह, अमरीका भी अब धर्म से दूर जा रहा है।

बाबाओं के साम्राज्य से निपटना आसान नहीं है। हमारे संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 51क (मौलिक कर्त्तव्य) में यह शामिल है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। बाबा और उनके संरक्षक इस प्रावधान का खुलेआम उल्लंघन करते हैं।

देश में कई ऐसे सामाजिक समूह हैं जो बाबाओं का पर्दाफाश कर उनका विरोध करते रहे हैं। इनमें हवा से राख पैदा करने और आग पर चलने जैसे चमत्कारों की असलियत लोगों के सामने रखना शामिल हैं। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ऐसी ही संस्था है। उससे जुड़े डॉ नरेन्द्र दाभोलकर को सनातन संस्था की तरह के दकियानूसी समूहों के कार्यकर्ताओं ने क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया था। इसी तरह की ताकतों ने कामरेड गोविन्द पंसारे, गौरी लंकेश और प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या की। डॉ दाभोलकर की हत्या के बाद, महाराष्ट्र विधानसभा ने अंधश्रद्धा और चमत्कारिक इलाज के खिलाफ एक कानून पारित किया।

पूरे देश में ऐसे कानूनों की ज़रुरत है। हमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना होगा। साथ में हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा हासिल हो। वर्तमान व्यवस्था, जिसमें अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब को हमें बदलना होगा। हमें महात्मा गाँधी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नीतियां अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई जाएँ। तभी हम समाज में सुरक्षा का भाव स्थापित कर सकेंगे। (लेखक- राम पुनियानी/ ईएमएस)

ज्वलंत मुद्दा - कई आईएएस की नियुक्तियों पर उठते सवाल!

यूपीएससी में एक नहीं अनेक कारनामें नाम से जगदीश्वर चतुर्वेदी की फेसबुक वाल पर अनेक उन अधिकारियों का उल्लेख किया गया है,जिन पर नियमों को ताक पर रखकर या फिर तथ्य छिपाकर नियुक्ति पाने का आरोप है।सच क्या है यह तो उच्च स्तरीय जांच के बाद ही पता चल पाएगा लेकिन लग रहे आरोपो में इस समय सबसे ऊपर

आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर है,जिनके चयन को लेकर शुरू से विवाद है,जो अभी तक भी थमने का नाम नही ले रहा है।इसी विवाद के चलते पूजा खेड़कर को रोब गालिब करने व पद की सीमाओं से परे जाकर प्रदर्शन करने के मामले में उनके कथित फर्जी कुछ प्रमाण पत्रों के कारण ट्रेनिंग से वापस बुला लिया गया,उनकी मां को गिरफ्तार होना पड़ा और संघ लोकसेवा आयोग ने भी उन्हें नोटिस जारी कर उन्हें मुसीबत में डाल दिया है। पूजा खेडकर ने काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जमा किया था। इसमें कहा गया है कि वह किसी भी रूप में विकलांग नहीं है। जबकि संघ लोकसेवा आयोग में प्रतियोगी परीक्षार्थी के तौर उन्होंने घोषित किया कि उन्हें मानसिक बीमारी,दृष्टि दोष सहित कई विकलांगताएं हैं। पूजा खेडकर ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कोटा के अंतर्गत लिया था,जिसमे उनकी जाति बंजारा बताई गई है। जबकि उनके माता पिता दोनो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। ऐसे में उनके अभिवावकों की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होने का सवाल ही नही उठता। बताया जा रहा है कि यूपीएससी एक्जाम पास कर आईएएस बनने के पीछे एक भाजपा नेत्री की बड़ी भूमिका है।एक अन्य मामले में एक पुलिस इंस्पेक्टर की पुत्री दिव्या यादव आईएएस बनी है। लेकिन आरोप है कि उनका चयन अनुसूचित जाति कोटे में हुआ है।

इसी तरह विश्वजीत पण्डा ने सन 2016 में नीट राउरकेला से क्लियर किया। उसके बाद उनकी एक बड़ी कम्पनी में नौकरी लग गई।उनके पिताजी सरकारी मास्टर है और भाई सन 2015 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। फिर भी कागजो में ये गरीब हैं। उन्होंने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाया और 343 रैंक के साथ यूपीएससी 2023 में सेलेक्ट हो गए।लेकिन किसी ने भी उनके दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश नही की।वही विपिन दुबे सीएससी यूपीएससी 2022 में 361 रैंक पाकर अधिकारी बनें है। उनके दादा खंड विकास अधिकारी रहे है और पिता जी सेशन कोर्ट के बड़े वकील है ।उन्होंने स्वयं नीट श्रीनगर से पास किया। सम्पन्न होने के वावजूद ईडब्ल्यूएस कोटा से यूपीएससी 2023 में 238 रैंक पाकर आईएएस बन गए। प्रियांशु खाटी को ही ले,वे हिमांचल प्रदेश कैडर 2021बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड कैटेगरी से भर्ती हुए है,लेकिन देखने मे एक दम फिट हैं। वे सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव रहे हैं। अपनी एक पोस्ट में बताते हैं कि वो फिफ्थ फ्लोर पर बिना लिफ्ट के पहुंच जाते हैं। इसी तरह से दिव्यांशी सिंह ने 2020 में यूपीएससी पास करके आईआरएस बन गईं। ये भी विकलांग कोटे से सेलेक्ट हुईं है। इनका सोशल मीडिया पर गोल्फ खेलने का वीडियो खूब वायरल हुआ है।जबकि रवि कुमार सिहाग ने 2021 में आईआरटीएस के तौर पर एक साल नौकरी की। फिर भी इनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन गया और यूपीएससी में गरीब कोटे से अधिकारी बन गए हैं।

इसी तरह संजना यादव 126 रैंक के साथ सीएसई 2019 में ओबीसी कोटे से पास हुईं। जबकि उनके पिता खुद आईआरएस हैं। ऐसे में नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट प्राप्त करना क्या जांच का विषय नही है।विजय वर्धन ने भी सीएसई 2018 में 104वी रैंक साथ आईपीएस का सफर पूरा किया। इन्होंने भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया और 288वी रैंक के साथ आईएएस बन गए।वही एन उमा हराती के पिता सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं ,लेकिन इनका सिलेक्शन नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत हुआ है।इसी तरह आसिफ के यूसुफ केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ये भी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर सन 2020 में चयनित हुए । जांच प्रक्रियाओं के बाद इनका फर्जीवाड़ा साबित भी हो गया। फिर भी अभी तक नौकरी पर बने हुए हैं।उत्तराखंड कैडर की आईएएस अधिकारी नितिका खंडेलवाल का सिलेक्शन सन 2014 में दृष्टि दोष कैटेगरी के अंतर्गत हुआ, लेकिन आरोप है कि ये यूटयूब चैनल में बिना चश्में के कंटेंट क्रिएशन करती हैं।जिसे लेकर उंगलियां उठ रही है।

प्रफुल्ल देसाई भी सन 2019 बैच के 532वी रैंक के साथ अधिकारी हैं। ट्रैनिंग के दौरान उन्होंने 25किमी की ट्रैकिंग की और 30 किमी साइकिलिंग का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन फिर भी उन्हें आर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड कैटेगरी में नियुक्ति मिली।जबकि आयुषी जैन यूपीएससी सन 2020 में 85वी रैंक के साथ आईपीएस बनी थी। फिर सन 2022 में ये ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के आधार पर आईएएस हो गईं। इसी प्रकार दुर्गा प्रसाद अधिकारी सन 2021 में 205वी रैंक के साथ अनारक्षित सीट से आईपीएस बने थे। इन्होंने भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया और सन 2022 में 162वी रैंक के साथ आईएएस बन गए।लक्ष्मण तिवाड़ी भी पहले आईपीएस थे। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लिया और आईएएस बन गए।उक्त नियुक्तियों पर उठे सवालों को लेकर सम्बंधित अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा नही किया बल्कि उनकी नियुक्ति नियमो के अनुकूल है।अब सच क्या है यह तो विस्तृत एवं गहन जांच के बाद ही पता चल सकता है।लेकिन इतना कह सकते है कि जब देश की सबसे बड़ी नियुक्ति परीक्षा का ये हाल है तो बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं का राम ही मालिक है। (लेखक - श्रीगोपाल नारसन/ ईएमएस)

शब्द पहेली - 8078

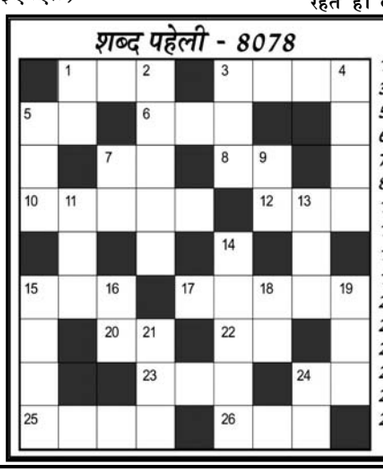

बाएँ से दाएँ

1.कंठ,गला-3
3.पक्षियों का शौर-4
5.शारीरिक ऊँचाई-2
6.पाचन शक्ति-3
7.मां की माता-2
8.प्यार,प्रेम(अंग्रेजी-2)
10.रचना करने वाला-5
12.शोरबा,तरी-3
15.खाद्य सामग्री-3
17.दोनों हाथों को पीटना-5
20.भाग्य(अंग्रेजी-2)
22.कदली,एक फल-2
23.उपासना,शीश झुकाना-3
24.घ्राणेन्द्रिय,नासिका-2
25.तहखाना-4
26.दया-3

ऊपर से नीचे

1.मर्यादा,सीमा-2
2.कहानी लिखने वाला-5
3.अचरज भरा कार्य-3
4.वर,इच्छित वस्तु देना-4
5.जलजला-3
7.मां के पिता-2
9.चिकनाई-2
11.हशीश,एक प्रकार का मादक पदार्थ-3
13.बोलने का तरीका-3
14.तमीजवाला-5
15.परंपरा,रिवाज-4
16.राजनीतिक पार्टी-2
18.आफत,मुसीबत-2
19.नाट्य,कथा मंचन-3
21.कमी-3
24.संबोधन-2

शब्द पहेली - 8077 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

रोहित ने बनाये हैं श्रीलंका के खिलाफ टी20 में सबसे अधिक रन

कोलंबो (ईएमएस)। भारतीय टीम मेजबान श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 27 जुलाई को खेलेगी। इस सीरीज में भारतीय टीम रोहित शर्मा के बिना ही उतरेगी। रोहित के नाम श्रीलंका के खिलाफ टी20 में सबसे अधिक रनों का रिकार्ड है। रोहित ने अब तक श्रीलंका के खिलाफ 19 मैच में कुल 411 रन बनाए हैं। उनका सबसे अधिक स्कोर 118 का रहा है। उनका औसत करीब 24 के आस पास का रहा है। एक शतक के अलावा उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया है। रोहित के बाद सबसे अधिक रन शिखर धवन ने बनाए हैं.

रोहित ने टी20 विश्व कप जीतने के बाद ही इस प्रारुप से संन्यास ले लिया था। इसी कारण वह इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में वह किसी भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दिखाई नहीं देंगे। अब वह केवल आईपीएल खेलते नजर आएंगे। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए भारत की टी20 टीमः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांडया, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई , अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज.

बीसीसीआई को चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम भेजने आईसीसी मनाये : पीसीबी

कराची (ईएमएस)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को चैंपियन्स ट्रॉफी के लिए मनाने और अपनी टीम भेजने की जिम्मेदारी उसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को सौंप दी है। पीसीबी ने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान की

ममता के शरणार्थी वाले बयान पर बांग्लादेश ने दर्ज कराई आपत्ति

नई दिल्ली(ईएमएस)। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पड़ोसी देश से आए संकटग्रस्त लोगों के लिए बंगाल अपने दरवाजे खुले रखेगा और उन्हें आश्रय देगा। उन्होंने एक रैली में कहा था अगर असहाय लोग पश्चिम बंगाल के दरवाजे खटखटाते हैं, तो हम निश्चित रूप से उन्हें आश्रय देंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल ऐसा इसलिए करेगा, क्योंकि अशांति वाले क्षेत्रों के आस-पास के क्षेत्रों में शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है। इस पर बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अपना विरोध जताया है। ममता ने कहा था कि वह हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से आने वाले असहाय लोगों को पश्चिम बंगाल में आश्रय देंगी। पड़ोसी देश ने इस मामले में भारत सरकार को एक आधिकारिक नोट भेजा है।बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान के साथ हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों में भ्रम की बहुत गुंजाइश है। इसलिए हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है।

इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी से उनकी टिप्पणी पर रिपोर्ट मांगी है। राजभवन ने कहा कि विदेशी मामलों से संबंधित किसी भी मामले को संभालना केंद्र का विशेषाधिकार है। राज्यपाल कार्यालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, विदेश से आने वाले लोगों को आश्रय प्रदान करने की जिम्मेदारी लेने वाले मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक बयान बहुत गंभीर प्रकृति का संवैधानिक उल्लंघन दर्शाता है।बता दें कि बांग्लादेश में विशेष रूप से राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर हिंसा बढ़ गई है। सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। शेख हसीना सरकार का समर्थन करने वाले छात्रों का एक जवाबी विरोध भी सड़कों पर उतर आया और प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। विरोध प्रदर्शन एक महीने से अधिक समय से चल रहा है, लेकिन पिछले सप्ताह ढाका विश्वविद्यालय में पुलिस कार्रवाई के बाद यह और बढ़ गया।

सरकार मौजूदा सिस्टम से इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित नहीं करा सकती

नई दिल्ली,(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। इस फैसले पर राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एनडीए को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा सिस्टम के तहत इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित नहीं करा सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पेपर लीक हुआ है।

सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली से मामले की जांच करने को कहा है कि इन मुद्दों से कैसे निपटा जाए। कोर्ट ने इसके सबूत मांगे हैं कि पेपर किस हद तक लीक हुआ था। सिब्बल ने कहा सवाल यह है कि इस सरकार में हर परीक्षा में पेपर लीक क्यों होता है। उन्होंने कहा कि इसमें कौन शामिल है और पेपर लीक किसके फायदे के लिए हो रहा है। बिना योग्यता वाले लोग कौन हैं जिन्हें नौकरी मिली। एनटीए को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने एक आईएएस अधिकारी को झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सेवाओं में आते देखा है। उन्होंने कहा कि आपको इस बीमारी से निपटना है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार नीट-यूजी 2024 की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें विवादों से घिरी इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसकी विश्वसनीयता के व्यवस्थित तरीके से प्रभावित होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है। कोर्ट का यह अंतरिम फैसला है और बाद में विस्तृत फैसला सुनाया जाएगा।

सेंसेक्स गिरावट के साथ 80,148 पर बंद

मुंबई (ईएमएस) । बजट के अगले दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिला। सेंसेक्स 280 अंक की गिरावट के साथ 80,148 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी में 65 अंक की गिरावट रही है, ये 24,413 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में गिरावट और 20 तेजी देखने को मिली। एनएसई के सेक्टोरल इंडेक्स में बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा 0.89 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। प्राइवेट बैंक में 0.76 प्रतिशत, फाइनेंशियल सर्विस में 0.60 प्रतिशत की गिरावट रही।

रेलवे बना रहा है दस हजार नॉन-एसी कोच

नई दिल्ली(ईएमएस)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करोड़ों रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज दी है। रेल मंत्री ने मिडिल क्लास और कम आय वाले परिवारों को खुशखबरी देते हुए बताया है कि रेलवे अभी ढाई हजार नॉन-एसी कोच बना रहा है और अगले तीन सालों में दस हजार और एक्स्ट्रा नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे। रेलवे का उद्देश्य यह है कि कम आय वाले परिवार और मिडिल क्लास किफायती कीमत पर सुरक्षित यात्रा कर सकें। ट्रेनें हजार किलोमीटर की यात्रा के लिए लगभग 450 रुपये की लागत पर विश्व स्तरीय सुविधाएं दे रही हैं।

रेल मंत्री ने आगे कहा, एसी और गैर एसी कोचों का अनुपात आम तौर पर 1/3और 2/3 रहा है। उस अनुपात को बनाए रखा गया है। गैर एसी यात्रा की मांग अब बढ़ गई है। अधिक से अधिक लोग यात्रा कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोग गैर एसी सेगमेंट के लिए यात्रा सेवाओं की मांग कर रहे हैं। इसलिए हमने एक विशेष अभियान चलाया है। हम 2,500 गैर-ण कोच बना रहे हैं और आने वाले तीन वर्षों में हम नियमित उत्पादन कार्यक्रम के अलावा 10,000 अतिरिक्त गैर-एसी कोच बनाएंगे। रेल मंत्री ने कहा कि साल 2014 से पहले रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय पर निवेश 35,000 करोड़ रुपये के आसपास हुआ करता था। आज यह 2.62 लाख करोड़ रुपये है। यह रेलवे के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय है। मैं रेलवे में इस तरह के निवेश के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का बहुत आभारी हूं।

सोने और चांदी की तेज शुरुआत

नई दिल्ली (ईएमएस)। घरेलू बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की तेज शुरुआत हुई। आम बजट के बाद सोने और चांदी की कीमतें गिरी थी पर आज इसमें सुधार देखा गया। सुबह सोने के वायदा भाव 68,800 रुपये के करीब। वहीं चांदी के वायदा भाव 85,350 रुपये के आसपास बने हुए थे। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने व चांदी के वायदा भाव की तेज शुरुआत हुई।

सोने के वायदा भाव की शुरुआत आज बढ़त के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अगस्त अनुबंध आज 280 रुपये बढ़कर 68,790 रुपये के भाव पर खुला।

एक समय ये अनुबंध 232 रुपये की तेजी के साथ ही 68,742 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। ये 68,832 रुपये के भाव पर दिन के उच्च और 68,652 रुपये के भाव पर दिन के निचला स्तर पर पहुंचा। सोने के वायदा भाव इस महीने 74,471 रुपये के भाव पर सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे थे।

वहीं चांदी के वायदा भाव की शुरुआत में आज तेजी रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर अनुबंध आज 281 रुपये की तेजी के साथ 85,200 रुपये पर खुला। इस साल चांदी के वायदा भाव ने 96,493 रुपये के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया था।

दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। कॉमेक्स पर सोना 2,410.70 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला जबकि इसका पिछला बंद भाव 2,407.30 डॉलर प्रति औंस था। कामेक्स पर चांदी के वायदा भाव 29.42 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव भी 29.33 था।

शॉर्ट और लांग टर्म कैपिटल गेन में बदलाव.. निवेशकों पर असर

मुंबई (ईएमएस)। आम बजट 2024 में कैपिटल गेन पर टैक्स में कई अहम बदलाव हुए हैं। इसका असर सीधे तौर पर निवेशकों को होने वाले मुनाफे पर होगा। बजट में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है, जो पहले 15 प्रतिशत था। यानी अब कोई भी निवेशक 12 महीने से पहले किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयरों को बेचकर मुनाफा कमाता है, उस मुनाफे पर 20 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना है। बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटलगेन टैक्स को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया है। अब निवेशकों को 12 महीने से ज्यादा समय तक होल्ड किए गए शेयरों को बेचने पर हुए मुनाफे पर 12.5 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

मोदी सरकार ने टैक्स में मामूली इजाफा कर निवेशकों को राहत भी दी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलने वाली टैक्स छूट को अब बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये किया गया है, जो कि पहले 1 लाख रुपये थी। फ्यूचर और ऑप्शन पर लगने वाली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) को बढ़ाकर 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत कर दिया गया है। डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शन को सेल पर विक्रेता की ओर से 0.0625 प्रतिशत एसटीटी अदा किया जाएगा। वहीं, इस पर 0.125 प्रतिशत एसटीटी ऑप्शन खरीदार की ओर से दिया जाएगा। बिल के मुताबिक, नई दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी। सरकार ने पर्सनल टैक्स के मोर्चे पर भी जनता को राहत दी है।

पेट्रोल डीजल की कीमतों में आया बदलाव

नई दिल्ली (ईएमएस)। घरेल बाजार में बुधवार कुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव आया है हालांकि देश के चारों महानगरों में कीमतें पहले की तरह ही हैं। राजधानी दिल्ली सहित चारों महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है पर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा और गुजरात समेत कुछ राज्यों में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं जबकि जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में ईंधन की कीमतें कम हुई हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 94.72 रुपये जबकि डीजल के दम 87.62 रुपये प्रति लीटर पर हैं। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये और डीजल की कीमत 91.76 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.76 रुपये, तो वहीं डीजल की कीमत 92.35 रुपये प्रति लीटर है।

उत्तर प्रदेश के नोएडा में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर, डीजल 88.23 रुपये प्रति लीटर, लखनऊ में पेट्रोल 94.64 रुपये प्रति लीटर, डीजल 87.66 रुपये प्रति लीटर, आगरा में पेट्रोल 94.55 रुपये प्रति लीटर है। डीजल 87.57 रुपये प्रति लीटर है। वाराणसी में पेट्रोल 95.50 रुपये प्रति लीटर है। डीजल 88.35 रुपये प्रति लीटर है जबकि पटना में पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर है। डीजल: 92.04 रुपये प्रति लीटर है।

25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क पूरी तरह हटाने का ऐलान

नई दिल्ली (ईएमएस)। अपने बजट 2024 भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोबाल्ट, लिथियम और तांबे सहित 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क (कस्टम डयूटी) पूरी तरह हटाने का ऐलान किया है। 2024 में देश के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए यह बड़ी घोषणा की गई है। सीमा शुल्क छूट के अलावा, मंत्री ने इनमें से दो खनिजों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में कटौती की भी घोषणा की। अपने बजट भाषण में सीतारमणनेकहा किये महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ मृदा तत्व परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा,अंतरिक्ष,रक्षा, दूरसंचार औरउच्च तकनीकवाले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सीतारमण ने कहा, ''छ्राब्ब (छूट से) ऐसे खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन को बढ़ावा मिलेगा तथा इन रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।''

बता दें कि सीमा शुल्क के हटने से देश में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन सस्ता हो जाएगा। लिथियम आयन बैटरी को बनाने में मुख्य तौर पर दो घटकों- लिथियम और कोबाल्ट का उपयोग होता है। सीमा शुल्क के हटने से इनकी कीमतों में कमी आएगी जिससे लिथियम बैटरी से चलने वाले कार, बाइक और स्कूटर के भी सस्ते होने की उम्मीद है। इसका फायदा देश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लाखों ग्राहकों को होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा बैटरी से चलने वाले ड्रोन की भी कीमतों में कमी आएगी।

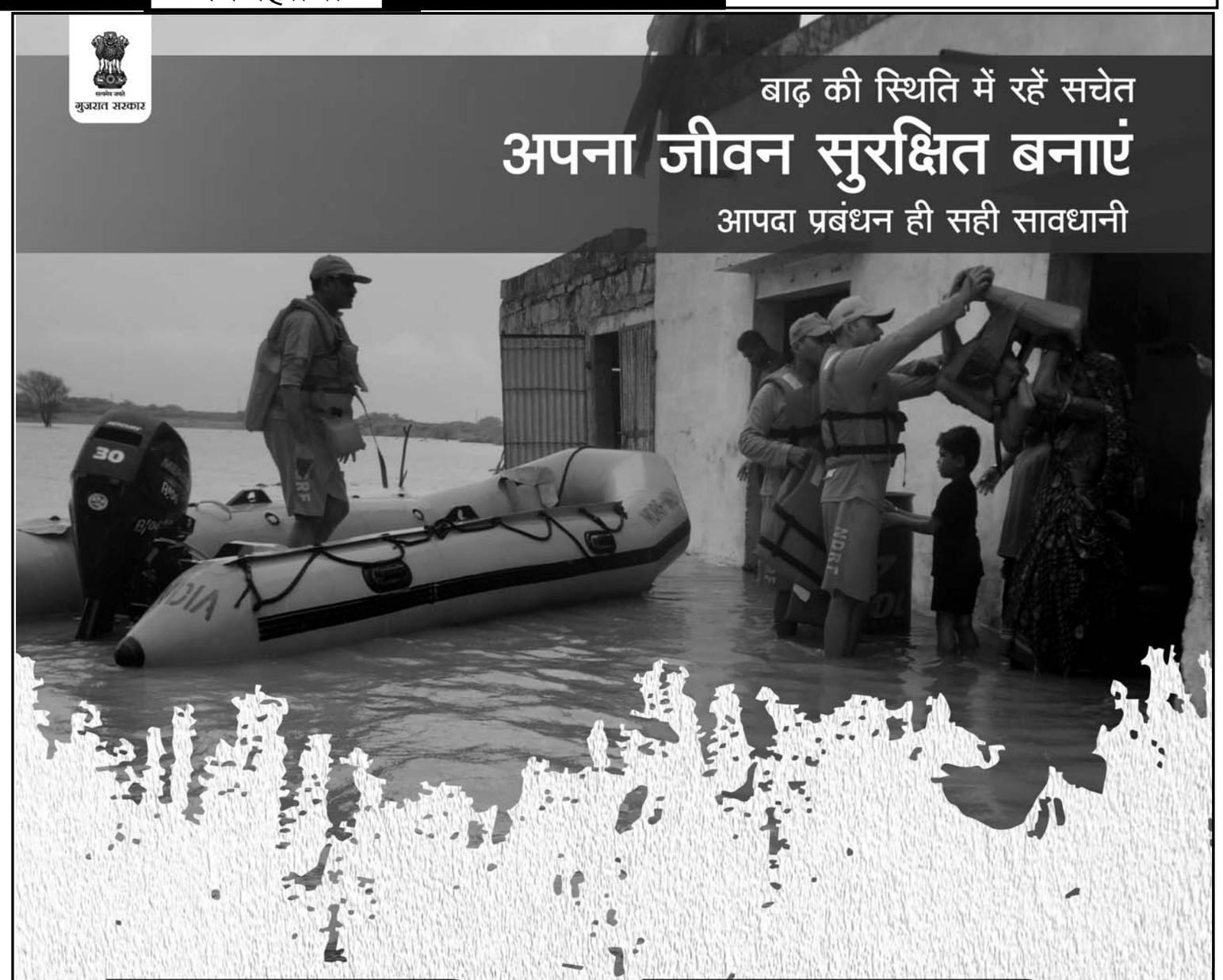

बाढ़ की स्थिति से पहले

- अफवाह न फैलाएं, शांत रहें, घबराएँ नहीं
- स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहकर उनके निर्देशों का पालन करें
- उस सुरक्षित मार्ग का पता लगाएं जो आसपास में सबसे निकट स्थित सुरक्षित स्थल तक पहुंचता हो
- मौसम और बाढ़ की चेतावनी की नवीनतम जानकारी के लिए रेडियो सुनें या टीवी देखें
- अपने मोबाइल फोन को चार्ज करके रखें
- सर्पदंश और उल्टी-दस्त की अतिरिक्त दवाई के साथ प्राथमिक उपचार किट तैयार रखें
- छतरी के साथ-साथ साँप जैसे विषैले जीवों से बचाव हेतु अपने पास एक छड़ी भी रखें
- शुद्ध पानी, पैकेज्ड फ़ूड, मोमबत्ती, माचिस, केरोसिन, लालटेन, मजबूत रस्सी, टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी अपने पास रखें
- पशुओं को खूँटे से ना बाँधें

स्थानांतरण करने की स्थिति में

- लोगों और पशुओं को ऐसे ऊँचे स्थानों पर लेकर जाएँ, जहाँ उन्हे बाढ़ से सुरक्षित आश्रय मिल सके
- घर के सभी खिड़की-दरवाजे अच्छे से बंद करें और दर्शाये गए मार्ग से सुरक्षित स्थान पर पहुंचे
- गटर को रेत की थैलियों से बंद कर दें ताकि बाढ़ का पानी गटर में प्रवेश ना कर सके
- कपड़े, आवश्यक दवाइयां, कीमती वस्तुओं और निजी दस्तावेजों की वाटरप्रूफ पैकिंग कर अपने साथ रखें
- फर्नीचर एवं घरेलू उपयोग के वस्तुओं को पलंग या टेबल के ऊपर ऊंचाई पर रखें
- घर छोड़ने से पहले बिजली की आपूर्ति और गैस सिलेंडर को बंद करें
- जोखिम भरे जलाशयों से दूर रहें

बाढ़ के दौरान

- गटर और पानी के निकासी मार्ग से दूर रहें
- बिजली के करंट से बचने के लिए बिजली के खंभे और जमीन पर पड़े बिजली के तार से दूर रहें
- संभव हो तो पानी को उबालें और फिर उसके तापमान को सामान्य करने के बाद पिएँ या पानी को अन्य किसी दूसरी प्रक्रिया से कीटाणु मुक्त करने के बाद पिएँ
- आसपास के स्थान को कीटाणु मुक्त रखने के लिए चूने और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें
- बच्चों को भूखा न रखें
- ताज़ा पका हुआ भोजन और पैकेज्ड फ़ूड को प्राथमिक्ता दें, भोजन को ढक कर रखें

बाढ़ के बाद

- स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और आपात सेवाओं से जुड़े कार्यकर्ताओं की सलाह ध्यान से सुनकर उसका पालन करें
- मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें
- बच्चों को बाढ़ के पानी के नजदीक न जाने दें
- बिजली के टूटे खंभों, क्षतिग्रस्त पुल-नालों, टूटे कांच और धारदार वस्तुओं एवं कबाड़ से सावधान रहें
- क्षतिग्रस्त बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें, इलेक्ट्रिशियन से जांच कराने के बाद ही ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करें
- बाढ़ के पानी में भीगे खाद्य पदार्थों का सेवन न करें
- आपात समय पर राहत और बचाव के लिए यहां दर्शाये गए आपातकालीन कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर पर सूचित करें

आपातकालीन संपर्क (लैंडलाइन फोन के लिए)* जिला कंट्रोल रूम – १०७७ / राज्य कंट्रोल रूम – १०७०

आपातकालीन नंबर को मोबाइल से डायल करते समय ज़िले का कोड अवश्य जोड़ें

जिम्मेदार बनें

अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें

प्रशासन को सहयोग करें

ताकि साथ मिलकर जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान हो सके।

नवीनतम और विश्वसनीय
जानकारी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडलों से प्राप्त की जा सकती है

@infogujarat | gujaratinformation.official | gujarat.information

गुजरात में भारी बारिश.....देवभूमि द्वारका में मकान गिरने से तीन की मौत

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। देवभूमि द्वारका में एक मकान धराशायी होने से तीन लोगों की मौत हो गई है। गुजरात के सौराष्ट्र और सूरत से लगे जिले में ज्यादा बारिश हो रही है। इस कारण सूरत, नवसारी, भरूच और वलसाड में स्कूल-कालेज बंद किए गए हैं। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त कर रेड अलर्ट जारी किया है।

पिछले 24 घंटों में राज्य की 35 तहसील में 4 से 11 इंच तक हुई बरसात, सबसे ज्यादा सूरत के उमरपाड़ा में 11 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह के 2 घंटे में ही राज्य की 120 तहसीलों में 2 इंच तक बरसात हुई थी। सूरत में खाड़ी के करीब वाले निचले इलाके अभी भी जलमग्न हैं। इसके चलते लोगों से बिना जरूरी काम के घरों से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। सौराष्ट्र के कच्छ और जूनागढ़ जिलों में बाढ़ में मवेशियों के बहने की घटनाएं सामने आई हैं।

पोरबंदर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश जारी है। इसके चलते कई दशक बाद पोरबंदर को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जूनागढ़ की माणावदर तहसील में हालात खराब हो गए हैं, वहीं देवभूमि द्वारका जिले में वर्षा ने 30 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। 31 इंच बारिश कुल औसत वर्षा की तुलना में पिछले 5-6 दिनों में 50 इंच बारिश हो चुकी है।

गुजरात में भारी और लगातार बारिश के बीच भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अपने नवीनतम पूर्वानुमान को 28 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। 25 जुलाई को सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली, पोरबंदर और जूनागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है, इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, डांग, तापी, राजकोट, जामनगर, अमरेली, भावनगर, द्वारका, गिर सोमनाथ और दीव को संभावित भारी बारिश के लिए पीली चेतावनी के साथ चिह्नित किया गया है।

आईएमडी ने 27 जुलाई को थोड़ी राहत मिलने का अनुमान जाहिर किया है। 28 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका के साथ नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली और भावनगर के लिए ऑरेंज अलर्ट है।

दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बाद अब मध्य गुजरात की बारी, बोरसद में 4 घंटों 12 इंच बारिश

अहमदाबाद (ईएमएस) दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र को डुबोने के बाद मेघा ने अब मध्य गुजरात का रुख किया है मध्य गुजरात के आणंद और वडोदरा भारी बारिश के कारण पानी पानी हो गया है आणंद जिले के बोरसद में तो केवल 4 घंटों में 12 इंच बारिश होने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं भारी बारिश के कारण जलभराव होने से बोट की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है बोरसद की 20 जितनी सोसायटियों में घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जानकारी के मुताबिक आणंद जिले के बोरसद में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 4 इंच और उसके बाद 10 बजे से दोहर 12 बजे तक 8 इंच बारिश दर्ज हुई भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर ने बोरसद प्रांत अधिकारी, तहसीलदार और तहसील विकास अधिकारी समेत अधिकारियों को तहसील मुख्यालय ना छोड़ने और ऐहतियाती कदम उठाने का आदेश दिया है भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं जिसे देखते हुए बोरसद, अलारसा, कोसिन्द्रा और आंकलाव रास्ता बंद कर दिया गया है दूसरी ओर वडोदरा में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है भारी बारिश के कारण वडोदरा के पास जीएसएफसी के पास से गुजरने वाले हाईवे पर विजिबिलिटी की समस्या पैदा हो गई बारिश के कारण कार की हेडलाइट से ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है हाईवे पर गुजरने वाले वाहन हेड लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से गुजर रहे हैं। मध्य गुजरात के ही छोटाउदेपुर के नसवाड़ी में चार घंटे में 5 इंच बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के कारण नसवाड़ी के कई इलाकों में जलभराव हो गया है सड़कें नदी-नाले में तब्दील हो गई है नसवाड़ी के कई खेत पानी में डूब गए हैं जिससे फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने का खतरा है नसवाडी में भारी बारिश के कारण एक स्कूल में पानी भर गया है स्कूल की ओर आने वाले वाहनों को तीन फीट पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण जलजमाव की समस्या उत्पन्न हुई है पानी भर जाने से अभिभावकों को अपने बच्चों को लेने खुद स्कूल आना पड़ा। बच्चों को बाहर निकलने के लिए बड़े वाहनों का सहारा लेना पड़ा

गुजरात में अगले पांच दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान, उत्तर और मध्य गुजरात भी होंगे पानी-पानी

अहमदाबाद (ईएमएस) मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 5 दिन भारी बारिश की भविष्यवाणी की है दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र को जलमग्न करने के बाद बारिश ने अब मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात का रुख किया है आनेवाले दिनों में सौराष्ट्र, दक्षिण, उत्तर और मध्य गुजरात समेत राज्यभर में भारी बारिश का पूर्वानुमान है मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली और भावनगर में बहुत भारी बारिश का अनुमान है और इसके साथ ही रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है वहीं आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, भरूच, डांग, तापी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है इसके साथ ही अरवल्ली, खेड़ा, अहमदाबाद में भी भारी बारिश की संभावना है शुक्रवार को आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली, तापी, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, गिरसोमनाथ बोटाद में भी भारी बारिश की संभावना है मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार और रविवार को डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली, तापी और भावनगर जिलों में भारी बारिश की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट दिया है इसके अलावा अमरेली और बोटाद में भारी बारिश की आशंका के साथ येलो अलर्ट दिया गया है मछुआरों को पांच दिनों तक समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में इस समय तीन सिस्टम सक्रिय हैं और इस कारण भारी बारिश हो रही है खासकर इन तीन सिस्टम के चलते आणंद जिले में बहुत भारी बारिश के पूर्वानुमान के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है।

कांग्रेस का भाजपा सरकार पर ग्रासिम कंपनी का 280 करोड़ माफ कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार ने विशेष मामले में ग्रासिम कंपनी का रु. 280 करोड़ माफ कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है लोक लेखा समिति के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक पूंजा वंश ने कहा कि ग्रासिम कंपनी 1999 से हिरण-2 बांध के पानी का उपयोग कर रही थी सरकार 1999 से जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार कंपनी को पानी का बिल दे रही थी। नवंबर 2023 तक जल संग्रहण का 434.71 करोड़ रुपये बकाया था। मामला लोक लेखा समिति के सामने आने पर कंपनी पर बोझ डालने की सिफारिश की गई। कलेक्टर ने कंपनी पर 264.37 करोड़ का बोझ डाला राजस्व नियमों के मुताबिक एक बार बोझ लगने के बाद माफ नहीं किया जा सकता कांग्रेस के पूर्व विधायक पूंजा वंश ने कहा कि एक विशेष मामले में कंपनी को तराई क्षेत्र से फायदा पहुंचाने के लिए ग्रासिम के 280 करोड़ रुपये माफ कर दिये ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड वेरावल द्वारा पानी के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा मई-1999 से नवंबर-2023 तक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था। मई-1999 से मार्च-2023 तक सामान्य जल शुल्क, जुर्माना शुल्क, सामान्य जल शुल्क पर ब्याज और पानी की खपत पर जुर्माना ब्याज कुल रु. 434.71 करोड़ की राशि बकाया है अगर ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी द्वारा अप्रैल-1999 से विवादित अवधि के दौरान गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जल उपकर के अनुसार जल दरों की बकाया मूल राशि का भुगतान एक किश्त में किया जाता है, तो जुर्माना और ब्याज राशि माफ की जानी है। तदनुसार, नर्मदा, जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर प्रभाग, गांधीनगर द्वारा आदेश दिया गया। जिसके अनुसार समझौते के बाद ग्रेसीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड रुपये से. 157.15 करोड़ का भुगतान करना था और करीब रु. 280 करोड़ की राशि माफ की गई है पूंजा वंश ने सवाल किया कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या यह सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जिसकी इतनी बड़ी रकम माफ कर दी गई है? ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड हिरन नदी के किनारे अवैध रूप से कुओं का निर्माण किया और पानी का भी उपयोग किया इसके बावजूद कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय, कंपनी को भुगतान की जाने वाली राशि में से रु. 280 करोड़ की राशि माफ कर दी, इससे क्या साबित होता है? कलेक्टर, गिर-सोमनाथ द्वारा ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की संपत्ति पर रु. साल 2019 में 264.37 करोड़ का बोझ पड़ा है लेकिन सरकार बोझ के बराबर राशि तो दूर, बोझ से भी अधिक रुपये वसूलने में विफल रही। कंपनी से 107 करोड़ की रकम कम वसूली गयी है इस पूरे अध्याय में स्पष्ट रूप से काफी भ्रम है। भाजपा सरकार एक भ्रष्ट सरकार साबित हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता व पूर्व विधायक पुंजा वंश ने भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी टैक्स के रूप में रुपये नहीं देता है तो पानी का कनेक्शन व सीलिंग कर दी जाती है राज्य सरकार का ग्रासिम उद्योग से ऐसा क्या संबंध है कि करोड़ों रुपए माफ करने पड़ रहे हैं? माफ किए गए रुपए अगर वसूले गए होते तो प्राथमिक सुविधाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किए जा सकते थे। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सरकार ने इतनी बड़ी राशि कैसे माफ कर दी? लोक लेखा समिति ने भी राशि वसूलने की रिपोर्ट दी। जब गुजरात के लोगों को साफ पीने का पानी पाने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं, ऐसे में अधिकारी गुजरात के औद्योगिक घरानों को सरकारी खर्च और जोखिम पर पानी के उपयोग की कितनी सुविधा दे रहे हैं इस जमीन के बदले कंपनी ने दूसरी जमीन पर कब्जा कर लिया और पानी ले लिया, लेकिन पानी के लिए सरकार को भुगतान की जाने वाली 349 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया है यह पूरी गड़बड़ी सामने आने के बाद विधानसभा की लोक लेखा समिति ने तत्कालीन कलेक्टर समेत राजस्व-जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी राज्य सरकार ने हिरन-2 बांध के पास एक कुएं से पानी निकालने के लिए इंडियन रेयॉन को 100 × 100 फीट जमीन आवंटित की। इस ज़मीन पर कब्ज़ा करने के बजाय, कंपनी ने पास की 929 वर्ग मीटर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ एक कुआँ खोद दिया। गिरसोमनाथ जिले के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर ने 13 फरवरी 1997 को कंपनी को अवैध निर्माण की तत्कालीन कलेक्टर को सूचना दी थी।

2 अगस्त से भुज और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच नई ट्रेन की शुरुआत

अहमदाबाद (ईएमएस) पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए भुज और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच एक नई ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 20983 भुज-दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 अगस्त 2024 से प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को भुज से 17:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 12:20 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 20984 दिल्ली सराय रोहिल्ला-भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 अगस्त 2024 से प्रत्येक बुधवार व शनिवार को दिल्ली सराय रोहिल्ला से 15:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 11:30 बजे भुज पहुंचेगी।इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर एवं जनरल श्रेणी के कोच रहेंगे।बुकिंग 25 जुलाई, 2024 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी।

पंचमहाल जिले में पहुंची पुणे के वैज्ञानिकों की टीम

अहमदाबाद, २४ जुलाई।

पंचमहाल जिले में इस वायरस के १४ संदिग्ध और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से पांच बच्चों की मौत हो चुकी है। गुजरात में चिंता का विषय बना चांदीपुरा वायरस को लेकर मंगलवार को पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) की पांच सदस्यीय टीम पंचमहाल जिले के प्रभावित इलाकों में समीक्षा करने पहुंची है। पंचमहाल जिले में इस वायरस के १४ संदिग्ध और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से पांच बच्चों की मौत हो चुकी है।

४८ घंटे में बरस चुका १३ इंच पानी, खाड़ी नदियों में आई बाढ़ से निचले इलाके डूबे

सूरत, २४ जुलाई।

गुजरात में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। खासकर सौराष्ट्र-कच्छ और दक्षिण गुजरात के जिलों में जमकर हो रही बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। सूरत में तीन दिनों से भारी बारिश हो रही है। मंगलवार को भी तेज बारिश जा रही। पिछले चौबीस घंटों में यहां ६ इंच बारिश हुई। इस तरह पिछले ४८ घंटों में १३ इंच बारिश हो चुकी है।

पिछले ४८ घंटों की बारिश ने शहर की सूरत ही बदल कर रख दी है। मंगलवार को दिनभर बारिश होती रही। ८४ मिमी यानी साढ़े ३ इंच बारिश से शहर के वेसू, वीआईपी रोड, अलथान, चौक बाजार, अडाजन, लिंबायत, पर्वत पाटिया सहित अन्य इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। श्याम मंदिर बीआरटीएस से लेकर वीआईपी प्लाजा तक मुख्य सड़क और सर्विस रोड पर तीन दिन से पानी भरा है। जलजमाव के कारण कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति है।

रही सही कसर खाड़ी नदी की बाढ़ ने पूरी कर दी। मंगलवार को जिले की पलसाणा तहसील में पांच इंच और कामरेज में पौने तीन इंच बारिश होने से शहर से गुजरने वाली खाड़ियां (समुद्र में मिलने वाली कृत्रिम नदियां) में बाढ़ आ गई। सीमाड़ा खाड़ी ओवरफ्लो होने से सड़कों के साथ आसपास की सोसा?टियों में में पानी घुस गया।

लिंबायत में मीठी खाड़ी ओवरफ्लो तो नही हुई, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्र खाड़ी के लेवल से कम होने से घरों में ३ से ४ फीट तक पानी भर गया। सरथाणा में आदर्श निवासी आश्रम स्कूल १११ और अन्य क्षेत्रों ९० से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। ओवरफ्लो होने के चलते मीठी खाड़ी नदी की मछलियां भीमराड में मेट्रो साइट के पास सड़क पर आ गई थीं। स्थानीय लोग मछलियां पकड़ने टूट पड़े। दूसरी तरफ, पांडेसरा और उधना में खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी पानी भरने से स्थिति गंभीर हो गई। लिंबायत में पुलिस ने अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क किया। मंगलवार देर रात से बारिश थमी है, लेकिन खाड़ी के ओवरफ्लो होने के चलते उसके आसपास के इलाकों के लिए आज भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र-कच्छ और दक्षिण गुजरात में बुधवार को भारी बारिश की चेतावनी दी है।

गुजरात में रेलवे के लिए इस साल रु. 8,743 करोड़ आवंटन : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात में रेलवे परियोजनाओं के लिए भारी बढ़ोतरी के साथ इस साल 8743 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं इस वर्ष के बजट में प्रावधानों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बताया कि वर्ष 2009-2014 के दौरान गुजरात का खर्च सालाना औसत खर्च 589 करोड़ की तुलना में करीब 15 गुना बढ़ गया है रेल मंत्री ने बताया कि गुजरात में 30,826 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,948 किमी की (नए ट्रैक) सहित 42 परियोजनाएं चल रही हैं। इसके अंतर्गत गुजरात में 87 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा जिनमें अहमदाबाद, आनंद, अंकलेश्वर, असारवा, बारडोली, भचाऊ, भक्तिनगर, भाणवड, भरूच, भाटिया, भावनगर, भेस्तान, भीलडी, बीलीमोरा जंक्शन, बोटाद जंक्शन, चांदलोडिया, चोरवाड रोड, डभोई जंक्शन, दाहोद, डाकोर, डेरोल, धांगध्रा, द्वारका, गांधीधाम, गोधरा जंक्शन, गोंडल, हापा, हिम्मतनगर, जाम जोधपुर, जाम वंथली, जामनगर, जूनागढ़ जंक्शन, कलोल जंक्शन, कानालूस जंक्शन, करमसद, केशोद, खंभालिया, कीम, कोसंबा जंक्शन, लखतर, लिंबडी, लिमखेड़ा, मेहमदाबाद खेड़ा रोड, मेहसाणा जंक्शन, महुवा, मणिनगर, मीठापुर, मियागाम करजन जंक्शन, मोरबी, नडियाद जंक्शन, नवसारी, न्यू भुज, ओखा, पदधारी, पालनपुर जंक्शन, पालिताना, पाटन, पोरबंदर, प्रतापनगर, राजकोट जंक्शन, राजुला जंक्शन, साबरमती बीजी, साबरमती एमजी, सचिन, सामाखियाली, संजान, सावरकुंडला, सायनसिद्धपुर, सीहोर जंक्शन, सोमनाथ, सोनगढ़, सूरत, सुरेंद्रनगर, थान, उधना, उदवाडा, उमरगांव रोड, उंझा, उतराण, वडोदरा, वापी, वटवा, वेरावल, विरमगाम, विश्वामित्री इत्यादि शामिल हैं अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ट्रैक विकास के लिए, 2009-14 के दौरान 132 किमी की तुलना में 2014-2024 के दौरान 224 किमी, जबकि 2014-24 के दौरान 300 किमी का विद्युतीकरण किया गया है जबकि 2009-14 के दौरान गुजरात में केवल 13 किमी का विद्युतीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, 2014 के बाद से गुजरात में 989 रेल फ्लाईओवर और अंडर-ब्रिज का निर्माण किया गया है।

भूटान नरेश तथा प्रधानमंत्री को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर भावपूर्ण विदाई दी

गांधीनगर (ईएमएस) भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक एवं प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की तीन दिवसीय गुजरात यात्रा सम्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को वांगचुक तथा श्री तोबगे को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गुजरात से भावपूर्ण विदाई दी। इस अवसर पर राज्य के प्रोटोकॉल मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, भारत के भूटान स्थित राजदूत सुधाकर दलेला, राज्य के मुख्य सचिव राज कुमार, राज्य पुलिस महानिदेशक विकास सहाय, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनुराग श्रीवास्तव, अहमदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त अजय चौधरी, मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी ज्वलंत त्रिवेदी, अहमदाबाद जिला कलेक्टर सुश्री प्रवीणा डी. के. आदि उच्चाधिकारियों ने भी भूटान नरेश तथा प्रधानमंत्री को विदाई दी। गुजरात यात्रा पूर्ण कर रवाना होने से पूर्व भूटान नरेश वांगचुक तथा प्रधानमंत्री तोबगे ने हेलीकॉप्टर से अहमदाबाद शहर का विहंगावलोकन किया। दोनों भूटानी महानुभाव वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद का विकास देख कर प्रभावित हुए।

भारी बारिश के कारण तीर्थ स्थल पावागढ़ में दर्शन पर रोक लगा दी गई है

वडोदरा 24 जुलाई

गोधरा: गुजरात में भारी बारिश को लेकर किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक पूरे राज्य में भारी बारिश हो रही है. पंचमहल जिले में भी भारी बारिश हो रही है. इसलिए तीर्थ स्थल पावागढ़ में पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिस्टम द्वारा पहाड़ी पर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. भारी बारिश के कारण पहाड़ी सीढ़ियों से पानी बह रहा है.

पौराणिक तीर्थ स्थल और शक्तिपीठ माने जाने वाले पावागढ़ को लेकर तंत्र ने एक अहम फैसला लिया है. पावागढ़ में रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए पुलिस ने यह फैसला लिया है. पावागढ़ की सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत कठिन है और बारिश के दौरान इन सीढ़ियों से पानी बहता है। इसलिए इस दौरान किसी भी हादसे को रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था ने दर्शन पर रोक लगा दी है.

इसके साथ ही गुजरात के कई जिलों में बारिश हो रही है. वडोदरा में भारी बारिश के कारण विश्वामित्री नदी उफान पर है. विश्वामित्री नदी का जलस्तर 9 फीट तक पहुंच गया है. नदी का जलस्तर बढ़ने पर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। वडोदरा और मुंबई में भारी बारिश के बाद मुंबई-दिल्ली रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है. जिसके चलते वडोदरा में 11 ट्रेनें लेट हो गई हैं और दो ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. आज सुबह से ही मेघराजा ने मध्य गुजरात में महार की वर्षा की है। जिसमें वडोदरा, खेड़ा और आनंद जिलों में आज सुबह से ही भारी बारिश शुरू हो गई है.

मोदीकेयर के साथ मनाएं सेल्फ–केयर डे; ब्राण्ड के वैलनेस एवं स्किनकेयर प्रोडक्ट्स से करें अपनी खास देखभाल

क्या आप अपनी देखभाल के लिए तैयार हैं? आपने अभी–अभी स्किनकेयर शुरू की है या आप हेल्थगुरू हैं, मोदीकेयर आपके लिए पेश करते हैं वैलनैस एवं स्किनकेयर प्रोडक्ट्स की व्यापक रेंज। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपनी खुद की देखभाल करना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मोदीकेयर के आधुनिक प्रोडक्ट्स ने इसे बेहद आसान बना दिया है।

सेल्फकेयर डे– यह दिन आपकी अपनी देखभाल को समर्पित है। आप अपना पोषण बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने वर्कआउट रूटीन में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी त्वचा को डिजिटल डिवाइसेज़ से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखना चाहते हैं– मोदीकेयर के पास आपकी हर ज़रूरत का हल है। अपनी देखभाल सिर्फ ट्रैंड नहीं है; यह स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली जीने के लिए ज़रूरी है। तो मेदीकेयर के साथ हर दिन का जश्न अपने लिए मनाएं।

वैलनैस मोदीकेयर की वैल गमीज़ रेंज

सेल्फ केयर डे पर मोदीकेयर की ओर से विटामिन एवं मिनरल्स से भरपूर इन गमीज़ के साथ स्वादिष्ट एवं पोषक अंदाज़ में अपने प्रति प्यार का इज़हार करें। पोशण को मज़ेदार बनाते हुए वैल गमीज़, खासतौर पर उन लोगों की जीवनशैली एवं आहार की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, जो हमेशा कहीं व्यस्त रहते हैं।

इस रेंज को खासतौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो व्यस्त जीवनशैली की वजह से अपने आहार पर ध्यान नहीं दे पाते। मात्र रु 699 में उपलब्ध वैल गमी रेंज में चार वेरिएंट हैं– वैल हेयर, स्किन एण्ड नेल गमी, वैल डीटॉक्स गमी, वैल शार्प आई गमी और वैल यमी टमिन गमी।

मुख्यमंत्री ने द्वारका, जामनगर जिले का किया हवाई निरीक्षण

गुजरात के कई जिलों में ताबड़तोड़ बरसात, ३१ बांधों में चली चादर

अहमदाबाद, २४ जुलाई।

गुजरात राज्य में पिछले कई दिनों से चल रही भारी बरसात से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई जिलों में बरसात ने हालात बिगाड़ दिए। ताबड़तोड़ बरसात से चहुंओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने हवाई दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है।

गुजरात राज्य में पिछले कई दिनों से चल रही भारी बरसात से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई जिलों में बरसात ने हालात बिगाड़ दिए। ताबड़तोड़ बरसात से चहुंओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने हवाई दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है।

गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ समेत कुछ भागों में मंगलवार को भी जमकर बारिश हुई। देवभूमि द्वारका जिले की द्वारका तहसील में फिर से मूसलाधार बरसात देखा गया। यहां पर सबसे अधिक सवा छह इंच पानी गिरा। सौराष्ट्र के बाद अब कच्छ जिले के कई हिस्सों में भी पानी बरसा। जिले की मांडवी तहसील में भी करीब छह इंच बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए।

मंगलवार सुबह छह बजे से लेकर शाम आठ बजे तक राज्य की १७२ तहसीलों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई।मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जामनगर जिले की जोडिया, कच्छ की नखत्राणा तहसील में भी ५ इंच, मुंद्रा व सूरत की पलसाणा व नवसारी की खेरगाम में करीब ५ इंच वहीं शपर में ४ इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही तापी के डोलवन, अहमदाबाद के धोलका, सूरत के कामरेज व चोर्यासी, बारडोली व सूरत शहर, डांग की वघई, देवभूमि की भाणवड तहसील में ३ इंच से ज्यादा बारिश हुई। भारी बारिश के कारण द्वारका में सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाकों में ३ से ४ फीट तक पानी भर गया। इससे वाहनों का आवागमन बंद हो गया। पिछले शुक्रवार से मंगलवार तक ३८ इंच बारिश होने के साथ सीजन की कुल बारिश ५५ इंच से अधिक बारिश हो चुकी है।

गुजरात के देवभूमि द्वारका और जामनगर जिले में भारी बारिश के चलते हालात खराब हैं। कई गांव जलमग्न हो गए हैं। खेती को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने द्वारका और जामनगर जिले का हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने इन दोनों ही जिलों के अधिकारियों के साथ बैठकर कर लोगों को तत्काल मदद पहुंचाने, टूटी सड़कों, बिजली के खंभों की मरम्मत के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

गुजरात के विविध भागों में लगातार हो रही बारिश के कारण ३१ बांधों में चादर चल गई है। इन बांधों को हाई अलर्ट घोषित किया गया है। राज्य के जल संपत्ति विभाग की रिपोर्ट के अनुसार लबालब हुए बांधों के निचले इलाकों को हाई अलर्ट किया है। राज्य के सबसे बड़े नर्मदा (सरदार सरोवर) बांध मंगलवार की स्थिति में क्षमता का ५५ फीसदी भर गया है। राज्य के अन्य प्रमुख २०६ बांधों औसतन ३९.९३ फीसदी जल संग्रह हो गया। सौराष्ट्र के १४१ बांधों में क्षमता के मुकाबले ४६.४० फीसदी जल संग्रह दर्ज किया गया।

गुजरात में मौसम की अब तक 48 फीसदी से अधिक औसत बारिश, 50 जलाशय हाई अलर्ट पर

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है राज्य में मौसम की अब तक 48 प्रतिशत से अधिक औसत बारिश हो चुकी है आनेवाले 5 दिनों के दौरान राज्य में भारी से अतिभारी बारिश की संभावना है भारी बारिश के कारण राज्य के जलाशयों में प्रचुर मात्रा में पानी की आय हो रही है गांधीनगर स्थित स्टेट इमर्जेंसी ऑपरेशन सेंटर से मिली जानकारी के मुताबिक आज 24 जुलाई 2024 को सुबह 6 बजे राज्य में सीजन की कुल औसत 48 प्रतिशत से अधिक वर्षा दर्ज की गयी है जिसमें सबसे ज्यादा 75 फीसदी बारिश कच्छ जोन में दर्ज की गई है इसके अलावा सौराष्ट्र जोन में कुल 71 फीसदी, दक्षिण गुजरात में 57 फीसदी, उत्तर गुजरात और पूर्व-मध्य गुजरात में 25 फीसदी बारिश हुई है भारी बारिश के कारण गुजरात के अधिकांश बांधों में प्रचुर मात्रा में पानी की आय हुई है। तापी के उकाई बांध में हर घंटे 1,22,000 क्यूसेक से अधिक पानी की आय हुई है। दमनगंगा बांध में 42 हजार क्यूसेक पानी आया है करजन बांध में हर घंटे 1,16,000 क्यूसेक पानी की आय हो रही है भादर-2 बांध में 10 हजार क्यूसेक पानी और सरदार सरोवर बांध में 25 हजार क्यूसेक पानी की आय हो रही है राज्य में भारी बारिश के कारण 50 जलाशय हाई अलर्ट पर हैं इन जलाशयों में 90 फीसदी से जल भंडारण हो चुका है जिसमें 10 बांधों में चेतावनी संकेतक लगाए गए हैं जबकि 9 बांध अलर्ट पर हैं जूनागढ़ जिले के 19 में से 16 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं जल प्रलय से 96 गांव प्रभावित हुए हैं भारी बारिश के कारण जिले की 65 सड़कें बंद हो गई हैं। बारिश में अब तक कुल 27 लोगों को बचाया जा चुका है 1238 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पलायन करना पड़ा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कैबिनेट बैठक में राज्य में वर्षा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की

गांधीनगर 24 जुलाई : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वर्तमान में पूरे राज्य में व्यापक और ब्द्रुछह्लरुछ्लरु–%ल्क में भारी वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति की सर्वग्राही समीक्षा की गई।

इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा देते हुए प्रवक्ता मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भारी वर्षा के कारण जिन जिलों और क्षेत्रों में जलभराव और संपत्ति के नुकसान की विकट स्थिति पैदा हुई है, वहां संबंधित प्रभारी मंत्रियों को राहत और बचाव कार्यों में जिला प्रशासन के मार्गदर्शन के लिए पहुंचने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल की बैठक में सड़क, बांध, बिजली, जलापूर्ति और खेतीबाड़ी को हुए नुकसान सहित तमाम मुद्दों की गहराई से समीक्षा की गई।

राज्य में आज शाम 06 बजे तक 461.22 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो औसत वर्षा के मुकाबले 52.23 फीसदी है। राज्य में कच्छ क्षेत्र में सर्वाधिक 75.50 फीसदी औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि उत्तर गुजरात में 26.71 फीसदी, पूर्व मध्य गुजरात में 31.38 फी